

आम आदमी[®]

एक आम इंसान की सोच



22 के हो गए
हठार छत्तीसगढ़

RNI NO.: CHHIN/2013/50684



6

पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने की 170 किमी की पदयात्रा



12

छत्तीसगढ़ सरकार की गोधान न्याय योजना बनी नजीर



30

दिल की बीमारी से मासूम का जीना था मुश्किल



Taste Our Delicious Food at your Doorstep!

Order on





- | | |
|-------------------|---------------------|
| प्रबंध संपादक | : उमेश के बंसी |
| सर्कुलेशन इंचार्ज | : प्रकाश बंसी |
| रिपोर्टर | : नेहा श्रीवास्तव |
| कंटेंट राईटर | : प्रशांत पारीक |
| क्रिएटिव डिजाइनर | : देवेन्द्र देवांगन |
| मैगजीन डिजाइनर | : युनिक ग्राफिक्स |
| मार्केटिंग मैनेजर | : किरण नायक |
| एडमिनिस्ट्रेशन | : निरुपमा मिश्रा |
| अकाउंट असिस्टेंट | : प्रियंका सिंह |
| ऑफिस कॉर्डिनेटर | : योगेन्द्र बिसेन |

प्रधान कार्यालय

965/1 ककड़ चौक, श्याम नगर रोड,
कठोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन : 0771-4044047
ईल : khabar@aamaadmi.in
कार्यालय
प्लाट नं. 118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक

उमेश कुमार बंसी, विवाटर नंबर 10, एम.एम.
रियल रेटेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर
(छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए
विवार, लेखकों के अपने है। इसमें संपादक / मुद्रक की
सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद
की विचारी में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस
पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई
क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

अनुक्रमणिका ●●●●●

नवंबर 2022



मकरकै की रवेती से सालिक राम हुआ आर्थिक रूप से सशक्ति

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार की जनहितकारी नीति और फैसलों से प्रदेश के गरीब, किसान सहित सभी वर्गों के लोग खुशहाल हो रहे हैं। गौरतलब है कि गरियाबांद जिले अंतर्गत वनांचल में बसे ग्राम जैतपुरी के सालिक राम ध्रुव ने कृषि अधिकारियों

10



महाराजा अग्रसेन ने हमे सेवा करने

05

पत्थलगांव में भव्य रूप से अग्रसेन स्वर्ण जट्ठंति महोत्सव की ...



मदिरा के अवैध विकाय पर हो

08

वाणिज्य कर (आबाकरी) मंत्री श्री कवासी लखमा ने आज



नया अध्ययन: चबा-चबाकर खाइए

09

जब कैलारी बर्न करने की बात आती है तो लोगों का ध्यान...



रूपया गिर नहीं सह डॉलर मजबूत हो

17

भारतीय रूपये की गिरती कीमत को लेकर केन्द्रीय मंत्री सीतारमण



पीएम किसान योजना जारी हो गई है

20

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में पीएम...



हमर कक्षा नंबर एक

25

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से अपने प्रदेश की आम जनता

सवर्णों को आरक्षण



उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

जरीब सवर्णों को आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है और इसके साथ ही आरक्षण के समग्र आधिकारिक स्वरूप में फिर बदलाव की शुरूआत हो जाएगी। हालांकि, यह महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट बहुमत से किया है, तीन न्यायमूर्ति इस व्यवस्था के पक्ष में थे, जबकि प्रथान न्यायाधीश यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र ने इस आरक्षण के खिलाफ मत देते हुए इसे अवैध और भेदभावपूर्ण कहा दिया है। पांच जजों की पीठ की ओर से बहुमत से आए इस फैसले के बाद सवर्ण गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षण मिलना जारी रहेगा। अभी तक संशय बना हुआ था कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था तो अनुसूचित जातियों-जनजातियों व अन्य पिछड़ीं जातियों के लिए ही थी। संसद ने 103वें संविधान संशोधन के जरिये 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़ों (ईडल्ट्यूएस) को आरक्षण देने के लिए कनून बनाया था। सरकार के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिस पर अब फैसला आया है और इसका व्यापक सामाजिक-राजनीतिक असर भी विभिन्न राज्यों में दिखेगा। जाहिर है, जब संसद ने कनून बना दिया है, तो उस कनून को चुनौती आसान नहीं है। फिर भी दो न्यायमूर्तियों की राय विपरीत रही है, यह वास्तव में संकेत है कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का मामला आगामी दिनों में भी गरम रहेगा।

क्या आरक्षण से असंतोष को दूर किया जा सकता है? क्या आरक्षण की बढ़ती मांग को खारिज किया जा सकता है? इसी फैसले में न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा है, यह विचार करने की जरूरत है कि आरक्षण कब तक जरूरी है? उन्होंने यह भी कहा कि गरीब सवर्णों को दूर करने के लिए आरक्षण

के अंतिम समाधान नहीं है। यह सिर्फ एक शुरूआत है। मतलब आरक्षण का सवाल बहुत व्यापक है और हमें इसके लाभ-हानि पर विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पिछड़ी जातियों, जनजातियों और गरीब सवर्णों के बीच भी जो वास्तविक वर्चित हैं, उनके हम लाभ पहुंचा पाएं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। अपने देश में अभी भी वर्चितों की बड़ी संख्या है, जिसे मदद की जरूरत है। सरकारों के अपने स्तर पर वर्णिश करनी चाहिए कि किसी वर्ग को कागज पर आरक्षण देने से ज्यादा जरूरी है, उस वर्ग के जरूरतमंदों तक आरक्षण को पहुंचाना, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है?

सर्वोच्च न्यायालय के इस अहम फैसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं दलित समुदाय कुछ बुद्धिजीवियों के स्वर प्रतिकूल हैं। आखिर नाराजगी कहां है और क्यों है? के दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय पहले आरक्षण के 50 प्रतिशत से बढ़ाने से इनकर कर चुका है। ओबीसी वर्ग को जब ज्यादा आरक्षण देने की बात आती है, तब इंदिरा साहनी मामले में लागी 50 प्रतिशत की ऊरी सीमा का हवाला दे दिया जाता है, लेकिन जब 10 प्रतिशत आरक्षण गरीब सवर्णों को मिलेगा, तब आरक्षण की सीमा वैसे ही 60 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इसक सीधा सा अर्थ है, 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा का अब केर्ड व्यावहारिक अर्थ नहीं रह गया है। ऐसे में, आबादी के अनुपात में अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी को ज्यादा आरक्षण देने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी पिछड़ी जाति या समाज में यह संदेश न जाए कि गरीब सवर्णों को तो आरक्षण मिलने लगा, पर हमें नहीं मिला।

महाराजा अग्रसेन ने हमें सेवा करने की शिक्षा प्रदान की है: बृजमोहन अग्रवाल

पत्थलगांव में भव्य रूप से अग्रसेन स्वर्ण जयंती महोत्सव की शोभायात्रा व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे एवं निरंतर 50 सालों तक इस परंपरा को बनाये रखने के लिये उन्होंने समर्प्त अग्रवाल समाज को बधाई दी।



का

यक्रम की शुरूआत में उन्होंने अग्रसेन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समाज के सभी लोगों ने झूमते गाते हुए शोभायात्रा निकाली। मंच पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। जिसके पश्चात पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण भी किया गया।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस परिवर्तनशील समय में पचास साल तक किसी परंपरा को बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन पचास वर्ष स्वर्ण जयंती मनाने के बाद क्या हम कोई संकल्प ले पाए हैं? हम सब प्रभु राम और उनके पुत्र खुश के वंशज हैं। महाराजा अग्रसेन ने तो बली प्रथा के विरोध में इन्द्र से भी लड़ाई लड़ ली थी। लोग कहते हैं कि अग्रवाल समाज में अग्रसेन जी का वंशज कोई है तो बृजमोहन है, क्योंकि वो अग्रवाल जैसे नहीं वो क्षत्रिय जैसे लड़ता है। हम केवल अपने काम धंधे के बारे में सोचते हैं। क्या हमनें कभी सोचा है कि अग्रसेन जी पहले क्षत्रिय थे बाद में वैश्य हुए हैं। हमारे अंदर भी क्षत्रिय गुण होना चाहिए, और जिस

दिन हमारे अंदर क्षत्रिय गुण आ जाएगा उस दिन कोई सरकार हमको ब्लैक मेल नहीं कर पाएगी कोई अधिकारी हमको दबा नहीं पाएगा। आगे श्री अग्रवाल नें कहा कि हमारे अग्रवाल समाज को पूरे विश्व में अगर किसी चीज के लिए पहचाना जाता है तो परिवार के कारण पहचाना जाता है, कि संयुक्त परिवार अगर कहीं है तो अग्रवाल समाज में है। अपने बच्चों को बरहवीं तक बाहर पढ़ने मत भेजिए, इससे बच्चे परिवर्कित शिश्टों को भूल जाते हैं, परिवार के प्रति उनका लगाव कम हो जाता है। हमें इस बात का विचार करना होगा कि हमारे संस्कार क्या है? हमारे परिवार क्यूं टूट रहे हैं? हमारे समाज के गरीब लोगों के लिए हम आखिर कर क्या रहे हैं? अग्रसेन जी ने एक इंट एक मुद्रा के माध्यम से हमें ये सिखाया है कि अग्रवालों का सबसे बड़ा काम सेवा का काम है। उनके राज में कोई गरीब नहीं होता था कोई विपन्न नहीं होता था। श्री अग्रवाल जी आगे कहा कि मैं आपसे ये कहूँगा कि आप स्वर्ण जयंती मनाते हुए तीन काम करने का निश्चय करो, पहला गरीब कि पढ़ाई। दूसरा गरीब का इलाज, तीसरा गरीब की शादी। गरीब की मदद करने से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। जिसके लिए हमें एक ट्रस्ट बनाने की



“

दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कोण्डागांव विधायक मोहन मरकाम की पदयात्रा पिछले दिनों समाप्त हो गई। उन्होंने 4 दिनों में हर दिन करीब 50 किलोमीटर पैदल चलकर लगभग 170 किलोमीटर की पदयात्रा कर पूरी की है। कोण्डागांव के शीतला मंदिर से लेकर दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर तक चली इस पदयात्रा में मरकाम के साथ लगभग 450 कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल थे।

पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने की 170 किमी की पदयात्रा



मोहन मरकाम ने मांगी दंतेश्वरी मार्ड से सुख शांति की मन्त्र

यात्रा समापन पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि, वह नवरात्र के अवसर पर हर वर्ष कोंडागांव से सैकड़ों देवी भक्तों के साथ दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी के दर्शन करने जाते हैं। बीते 2 वर्ष कोरोना महामारी कारण वह माता के दरबार नहीं जा पा रहे थे। मोहन मरकाम ने कहा कि, उनकी दंतेश्वरी माता के प्रति सच्ची आस्था और श्रद्धा है। देवी माता सबकी मुराद पूर्ण करती हैं, इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की खुशहाली और जनता के सारे कष्टों को दूर करने मां से मन्त्र मांगी है।

राहुल की भारत जोड़ी यात्रा से कम चर्चित नहीं रही मरकाम की पदयात्रा

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ी यात्रा पर सबकी नजर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की पदयात्रा की चर्चा भी कम नहीं थी। वजह है कि कांग्रेस ने इस पदयात्रा में अपने धुर विरोधी सियासी दल को भी इसमें शामिल होने का न्योता भेजा था। दरअसल मोहन मरकाम अपने विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव से दंतेवाड़ा



तक 170 किलोमीटर की यात्रा केवल दिनों में पूरी की। इस दौरान उन्होंने जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी संवाद भी किया।

राहुल गांधी भी हैं मरकाम की पदयात्रा से प्रभावित

बीते दिनों कन्याकुमारी में भारत जोड़ी यात्रा की शुरूआत के दौरान मरकाम ने राहुल गांधी को जानकारी दी थी कि वह हर साल पदयात्रा आयोजित करते हैं, जिसमें एक दिन में वह 50

नहीं शामिल हुए अरुण साव, बयानबाजी रहेगी जारी

मोहन मरकाम इस इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को भी आमंत्रित किया था, लेकिन आमंत्रण के बाद भी भाजपा का कोई नेता इस पदयात्रा में शामिल नहीं हुआ। मोहन मरकाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बस्तर प्रवास थे।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं इसी मौके को लपककर भाजपा पर रिवर्स स्ट्रिंग दे मारा। जिला कांग्रेस कमेटी कोंडागांव के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने बीते बीते शनिवार को कोंडागांव में भाजपा नेताओं से मिलकर कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना को लेकर शामिल होने का निमंत्रण दिया था।

किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। मरकाम की बातें सुनकर राहुल गांधी भी बहद प्रभावित हुए थे।

इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मोहन मरकाम की एक दिन में 50 किलोमीटर चलने की बात को झूठ बताया था। अरुण साव ने कहा था कि झूठ बोलना कांग्रेस की फितरत रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता से झूठ बोला है, अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी से भी झूठ बोल रहे हैं।

मंदिरों के अवैध विक्रय पर हो सख्त कार्रवाई

आबकारी मंत्री श्री लखमा ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश



वाणिज्य कर (आबकारी) मंत्री श्री कवासी लखमा ने आज नया रायपुर स्थित आबकारी भवन में आयोजित बैठक में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। आबकारी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि मंदिरों का विक्रय निर्धारित मूल्य पर हो, यह सुनिश्चित करें। निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। श्री लखमा ने कहा कि मंदिरों के अवैध भंडारण, परिवहन और विक्रय पर भी कड़ी नजर रखी जाए। निदेशों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विक्रय को रोकने के लिए सतत भ्रमण और निरीक्षण करते रहें। सभी लाइसेंसी दुकानों में मंदिरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अन्य राज्यों से होने वाले मंदिरों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए आबकारी जांच चौकियों पर कड़ी निगरानी करने के निर्देश जिला आबकारी अधिकारियों को दिए। उन्होंने अन्य राज्यों से अवैध शाराब लाकर बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही एवं जिला बदर की सख्त कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में सचिव सह प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड श्री ए. पी. त्रिपाठी, अपर आयुक्त श्री राकेश कुमार मंडावी, श्री आर एस ठाकुर, संभाग व जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आबकारी विभाग के सचिव सह आयुक्त श्री निरंजन दास ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि आबकारी नीति का कड़ाई से पालन करवाया जाए। अवैध भंडारण, परिवहन और व जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री

राकेश कुमार
मंडावी, श्री
आर एस
ठाकुर, संभाग

नया अध्ययनः चबा-चबाकर

खाइए और कैलोरी जलाइये

“

जब कैलोरी बर्न करने की बात आती है तो लोगों का ध्यान सरपट सैर, साइकिल चलाना या ऐसे ही व्यायामों की ओर जाता है, चबाने का तो विचार तक नहीं आता। अब, एक नवीन अध्ययन बताता है कि दिन भर में हमारे द्वारा खर्च की जाने वाली कुल ऊर्जा में से लगभग 3 प्रतिशत ऊर्जा तो चबाने की क्रिया में खर्च होती है। कुछ सर्वत या रेशेदार चीज चबाएं तो थोड़ी और अधिक ऊर्जा खर्च होगी। हालांकि यह ऊर्जा चलने या पाचन में खर्च होने वाली ऊर्जा से बहुत कम है, लेकिन अनुमान है कि इसकी भूमिका हमारे पूर्वजों के चेहरे को नया आकार देने में रही।

ऐ

सा माना जाता रहा है कि हमारे जबड़ों की साइज और दांतों का आकार चबाने को अधिक कुशल बनाने के लिए विकसित हुआ था। जैसे-जैसे हमारे होमिनिड पूर्वज आसानी से चबाने वाले भोजन का सेवन करने लगे और भोजन को काटने-पीसने और पकाने लगे तो जबड़ों और दांतों का आकार भी छोटा होता गया। लेकिन यह जाने बिना कि हम दिनभर में चबाने में कितनी ऊर्जा खर्च करते

हैं, यह बता पाना मुश्किल है कि क्या वाकई ऊर्जा की बचत ने इन परिवर्तनों में भूमिका निभाई थी।

यह जानने के लिए मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की जैविक मानव विज्ञानी एडम वैन केस्टरेन और उनके दल ने 21 प्रतिभागियों द्वारा खर्च की गई ऑक्सीजन और उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का मापन किया। इसके लिए प्रतिभागियों को एक हेलमेट जैसा यंत्र पहनाया गया था। फिर उन्हें 15 मिनट तक चबाने के लिए चुइंगम दी। यह चुइंगम स्वादहीन, गंधहीन और कैलोरी-रहित थी। ऐसा करना जरूरी था अन्यथा पाचन तंत्र सक्रिय होकर ऊर्जा की खपत करने लगता। चबाते समय प्रतिभागियों द्वारा प्रश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया। यह दर्शाता है कि चबाने पर शरीर ने अधिक कार्य किया। जब चुइंगम नर्म थी तब प्रतिभागियों का चयापचय औसतन 10 प्रतिशत बढ़ा। सख्त चुइंगम के साथ चयापचय में 15 प्रतिशत तक वृद्धि देखी गई। यह प्रतिभागियों द्वारा दिन भर में खर्च की गई कुल ऊर्जा का 1 प्रतिशत से भी कम है लेकिन मापन-योग्य है। ये नरीजे साइंस एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं।

शोधकर्ताओं के मुताबिक इससे पता चलता है कि खाना पकाना और औजारों का इस्तेमाल शुरू होने से पहले आदिम मनुष्य चबाने में बहुत अधिक समय बिताते होंगे। यदि प्राचीन मनुष्य दिन भर में वर्तमान गोरिल्ला और ओरांगुटान जितना भी चबाते होंगे तो शोधकर्ताओं का अनुमान है कि वे दिन भर में खर्च हुई कुल ऊर्जा का कम से कम 2.5 प्रतिशत चबाने में खर्च करते होंगे। ये नरीजे इस विचार का समर्थन करते हैं कि चबाने में सुगमता आने से वैकासिक लाभ मिला। चबाने में लगने वाली ऊर्जा की बचत का उपयोग आराम, मरम्मत और वृद्धि जैसी अन्य चीजों पर हुआ होगा।

चबाने में मनुष्यों द्वारा खर्च होने वाली



ऊर्जा गणना से अन्य होमिनिड्स के विकास के बारे में भी एक झलक मिल सकती है। मसलन 20 लाख से 40 लाख साल पूर्व रहने वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दांत आधुनिक मनुष्यों की तुलना में चार गुना बड़े थे और उनके जबड़े विशाल थे। वे चबाने में अधिक ऊर्जा लगाते होंगे। अन्य शोधकर्ता इस बात से सहमत नहीं है कि सिर्फ ऊर्जा की बचत ने जबड़ों और दांत के विकास का रुख बदला। इसमें अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अन्य कारकों की हो सकती है, जैसे ऐसे आकार के जबड़े विकसित होना जो दांतों के टूटने या घिसने की संभावना कम करते हों। प्राकृतिक चयन में संभवतः ऊर्जा दक्षता की तुलना में दांतों की सलामती को अधिक तरजीह मिली होगी, क्योंकि दांतों के बिना भोजन खाना मुश्किल है, और ऊर्जा मिलना भी।

आम आँखें // नवम्बर // 2022



मक्के की खेती से सालिक राम हुआ आर्थिक लघु से सशक्त

वन अधिकार पट्टे
से मिले ढाई एकड़
जमीन में 18 विचंटल
से अधिक हुआ मक्के
का उत्पादन



मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार की जनहितकारी नीति और फैसलों से प्रदेश के गरीब, किसान सहित सभी वर्गों के लोग खुशहाल हो रहे हैं। गौरतलब है कि गरियाबंद जिले अंतर्गत वनांचल में बसे ग्राम जैतपुरी के सालिक राम ध्रुव ने कृषि अधिकारियों की सलाह पर वन अधिकार पट्टा के तहत मिले ढाई एकड़ जमीन में मक्के की खेती की। उनके खेत में मक्के की भरपूर पैदावार हुई।



३ न्हें 18 किवंटल उत्पादन मिला। पहले वे धान की खेती करते थे जिसमें उन्हें बहुत कम उत्पादन मिलता था। सालिक राम के परिवार में अब खुशी का माहौल है।

किसान सालिक राम ने बताया कि वे वन अधिकार पट्टा के तहत मिले जमीन पर इस बार उन्होंने ढाई एकड़ में कृषि विभाग द्वारा मिले निःशुल्क मक्के का बीज (केएमएच-3426) लगाया था। इस खेती से उसने लगभग 18 किवंटल मक्के का उत्पादन हुआ है। जिसमें से उन्होंने 8 किवंटल से ज्यादा खुले बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया।

किसान सालिक राम ने बताया कि धान के बदले इस नई फसल से मिले आमदनी से उनका परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। वे अब धान के बदले मक्के की खेती कर रहे हैं। इससे अच्छी आय की प्राप्ति हो रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 10 किवंटल मक्के को अब वे समर्थन मूल्य पर विक्रय किया। उन्हें धान के बदले मक्का की खेती के लिए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान राशि भी मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेती-किसानी को दिया जा रहा है। प्रोत्साहन के कारण सालिक राम इस कार्य में अपने बेटे आत्माराम को भी खेती किसानी से जोड़ रहे हैं और उसे खेती की बारिकीयों को समझा रहे हैं। आत्माराम ने कहा कि वे आसपास के किसानों को भी अन्य फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ताकि उन्हें भी अच्छे आमदनी हो सके। सालिक राम ने मक्के की खेती के साथ ही मछली पालन और मशरूम उत्पादन भी कर रहे हैं। जिससे उनको अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो रही है।



राज्य में पशुपालकों से अनवरत रूप से की जा रही है गोबर खरीदी

छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना बनी नजीर

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना देश-दुनिया के लिए नजीर बन गई है. देश के कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को एक सफल और मजबूत योजना के रूप में सराहा जा रहा है. गांव-गांव में की जा रही गोबर खरीदी और जैविक खाद के सतत निर्माण एवं उपयोग से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है.

गो

धन न्याय योजना की शुरूआत जिन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए की गई थी, इस योजना ने उन सभी लक्ष्यों में बहुत कम समय में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं. यह योजना गांवों में खुशहाली का सबब बन गई है. छत्तीसगढ़ का गौरव बन चुकी गोधन न्याय योजना की देशभर में सराहना हो रही है. पार्लियामेंट की स्थाई कृषि समिति ने छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना की तारीफ करने के साथ ही इसे पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की है. गोधन न्याय योजना के तहत बीते सवादो सालों में 87.28 लाख विवरण गोबर की खरीदी पशुपालकों ग्रामीणों एवं किसानों से की गई है, जिससे जैविक खाद सहित अन्य सामग्री का निर्माण महिला स्व-सहायता समूह द्वारा

गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 356.14 करोड़ का भुगतान

गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक गोबर विक्रेता पशुपालक किसानों सहित गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 356 करोड़ 14 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 18 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। गौठानों में 15 अकट्टूबर तक खरीदे गए 87.28 लाख किवंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेताओं को 174.56 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 159.41 करोड़ रुपए राशि की भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 163.58 करोड़ लाभांश राशि का वितरण किया गया है। स्वावलंबी गौठानों में स्वयं की राशि से 21.78 करोड़ रुपए का गोबर क्रय किया है।

गौठानों में अनवरत रूप से किया जा रहा है। गोबर खरीदी के एवज में अब तक 174.56 करोड़ रुपए का भुगतान गोबर विक्रेताओं को किया जा चुका है। क्रय किए गए गोबर से गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा लगभग 24 लाख किवंटल वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट एवं सुपर कम्पोस्ट प्लस का निर्माण किया गया है। जिसमें से 20 लाख किवंटल कम्पोस्ट खाद का उपयोग किसानों ने अपने खेतों में किया है। इससे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है।

छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरूआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन से हुई थी। इस योजना के तहत मार्च 2021 यानी 9 माह में 45.81 लाख किवंटल गोबर की खरीदी हुई, जिसका उपयोग वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए क्रमिक रूप से किया गया। वर्ष 2021-22 में 21.28 लाख किवंटल गोबर की खरीदी राज्य में हुई। योजना के सत



का उपयोग खाद बनाने हेतु किया गया है।

वर्मी कम्पोस्ट निर्माण एक सत्त प्रक्रिया है गोठानों में गोबर क्रय की मात्रा एवं कम्पोस्ट उत्पादन की मात्रा व रूपांतरण मौसम के आधार पर प्रभावित होता है। गोबर क्रय एवं कम्पोस्ट का उत्पादन गोठानों में निर्मित वर्मी टांका के आधार पर ही होता है।

सरगुजा जिले में अब तक 1,38,384 किवंटल गोबर महिला स्व-सहायता समूहों को वर्मी खाद निर्माण हेतु उपलब्ध कराया गया है। जिससे 57,248 किवंटल वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण हो चुका है जो कि 41 प्रतिशत है। इसी प्रकार बस्तर जिले में 82,876 किवंटल गोबर से 39,377 किवंटल वर्मी तथा बीजापुर में 38,811 किवंटल गोबर से 18468 किवंटल वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण कराया गया जो कि लगभग 48 प्रतिशत है।

गोबर से 24 लाख कम्पोस्ट खाद का उत्पादन-समूहों को 81.84 करोड़ की आय

गौठानों में महिला समूहों द्वारा 18.61 लाख किवंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 5.37 लाख किवंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट एवं 18,924 किवंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस खाद का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से क्रमशः 10 रुपए, 6 रुपए तथा 6.50 रुपए प्रतिकिलो की दर पर विक्रय किया जा रहा है। महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अणरबती, मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रही हैं। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्जी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन एवं पशुपालन के साथ-साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिला समूहों को अब तक 84.55 करोड़ रुपए की आय हो चुकी हैं। राज्य में गौठानों से 11,187 महिला स्व-सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 83,874 है। गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरूआत की जा चुकी है।

22 के हो गए हन्दार छतीसगढ़

1 नवंबर को अपने छतीसगढ़ ने 22 वर्ष पूरे कर लिए और प्रदेश में 22वें स्थापना दिवस को लेकर तैयारी जोरों पर है। हर साल की तरह इस साल भी राज्योत्सव का कार्यक्रम रायपुर के साझंस कॉलेज मैदान में होगा। राज्योत्सव के दौरान देशी और विदेशी कलाकार शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्योत्सव की तैयारियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस बार राज्योत्सव में 1500 आदिवासी कलाकार भी शामिल होंगे। जिसमें से 1400 कलाकार भारत और 100 कलाकार विदेशी होंगे।







राज्य के लिए करना पड़ा संघर्ष

छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। उस वक्त आर्थिक रूप से यह काफी पिछड़ा हुआ था। उस वक्त प्रति व्यक्ति आय 10,125 रुपये थी जो आज बढ़ कर 10552 रुपये हो गई है। इस तरह देखा जाए तो पिछले 22 सालों में छत्तीसगढ़ वासियों की आय में करीब 12 गुना की वृद्धि हुई है। इस विकास को हम पांच चरणों में देख सकते हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़े कदम

छत्तीसगढ़ अपने निर्माण के वक्त स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहद मामूली संसाधन वाला क्षेत्र था। 21 साल में इस दिशा में काफी काम हुआ है। जब राज्य का निर्माण हुआ था, उस वक्त यहाँ महज एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, लेकिन आज इसकी संख्या बढ़कर आधे दर्जन से भी अधिक हो गई है। प्रदेश में आईआईएम,

आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी जैसी कई बड़ी संस्थाएं खुल गई हैं। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में भी काफी विकास हुआ है।

36 किलों का गढ़ छत्तीसगढ़

इतिहासकारों के मुताबिक कल्याणी राजाओं द्वारा 36 किलो या कई गांवों को मिलाकर गढ़ बनाए गए थे। इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल के तौर पर भी जाना जाता था। बताते हैं, राजाओं के समय में छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर के पास स्थित एक शहर रतनपुर, कल्युची हुआ करती थी। हालांकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। जल-जंगल और जमीन है पहचान : किले और गढ़ के अलावा छत्तीसगढ़ की और भी कई पहचान है। कहते हैं, जब जंगलों में धूप खिले...जब नदियां बहती जाएं...जब बैलों की पूजा हो...परंपराएं निर्भाई जाएं...तो समझ जाइएगा छत्तीसगढ़ है। जब धान की

2000 में हुआ था छत्तीसगढ़ का गठन

1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। आधिकारिक दस्तावेज में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम प्रयोग 1795 में हुआ था। छत्तीसगढ़ शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में कोई एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कल्याणी काल में छत्तीसगढ़ आधिकारिक रूप से 36 गढ़ों में बंटा था, यह गढ़ एक आधिकारिक इकाई थे न कि किले या दुर्ग। इन्हीं हाथों 36 गढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ नाम कि व्युत्पत्ति हुई।

खुशबू की महक उठे...बिटिया तीज में मेहदी लगाकर चहक उठे...सुआ नृत्य में झूमते-झूमते जब महानदी की लहर उठे....तो समझ जाइएगा छत्तीसगढ़ है। पोला-हरेली, चीला और फरा...बस्तर स्वर्ग सा सुंदर हरा-भरा...दंतेश्वरी के आशीष से जब दुख हरते जाएं...तो समझ जाइएगा छत्तीसगढ़ है।

आदिवासियों की झोली में रीति और रिवाज हैं। खेतों से आती खुशहाली की आवाज है। तीजन बाई की पंडवानी में जब चारों दिशाएं बंधती जाएं...समझ जाइएगा छत्तीसगढ़ है।

छत्तीसगढ़ का इतिहास : प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ह्यादक्षिण कौशललह के नाम से जाना जाता था। रामायण और महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। 6वीं और 12वीं शताब्दियों के बीच सरभपुरिया, पांडुवंशी, सोमवंशी, कलचुरी और नागवंशी शासकों ने यहाँ शासन किया। साल 1904 में यह प्रदेश संबलपुर उड़ीसा में चला गया और ह्यासरगुजाहा रियासत बंगाल से छत्तीसगढ़ के पास आया।

छत्तीसगढ़ पूर्व में दक्षिणी झारखण्ड और ओडिशा से, पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, उत्तर में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी झारखण्ड, दक्षिण में आंध्रप्रदेश से घिरा है। कहते हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास केवल 21 साल पुराना नहीं है। जब छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश का हिस्सा था, तब भी छत्तीसगढ़ीयों का दिल अपने राज्य के लिए धड़कता था। डॉ. पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, खूबचंद बघेल जैसी विभूतियों ने छत्तीसगढ़ के लिए जन-जागरण के साथ इसे पाने के लिए लंबा संघर्ष किया था।

रूपया गिर नहीं रहा

डॉलर मजबूत हो रहा है निर्मला सीतारमण

मारतीय रुपये की गिरती कीमत को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसउल उन्होंने रुपये की गिरती कीमत की वजह को डॉलर का मजबूत होना बताया है। इस साल ग्रीनबैंक के मुकाबले रुपये की कीमत में आठ फीसदी की गिरावट हुई है। वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में हिस्सावह लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत हैं और दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में महंगाई कम है। उनसे जब रुपये के कमज़ोर होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं इसे रुपये की गिरावट के रूप में नहीं देखती हूं, मैं इसे डॉलर की लगातार मजबूती के रूप में देखती हूं। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, दुनियाभर की अन्य सभी मुद्राएं डॉलर के मुकाबले प्रदर्शन कर रही हैं। सीतारमण ने कहा, मैं तकनीकी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन तथ्य यह है कि भारत का रुपया शायद इस डॉलर की मजबूती को झेल चुका है, वहाँ एक्सचेंज रेट (विनियम दर) डॉलर की मजबूती के पक्ष में है और मुझे लगता है भारतीय रुपये ने कई अन्य उभरती बाजार मुद्राओं की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।

7 अक्टूबर तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 532.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक साल पहले 642.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारतीय रिजर्व बैंक और सीतारमण पहले विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के लिए अमेरिकी डॉलर की मजबूती से पैदा होने वाले मूल्यांकन परिवर्तनों को ठहरा चुके हैं।

आम आदमी^{प्रतिक्रिया} // नवम्बर // 2022



छतीसगढ़ में
समृद्ध होते
किसान



डॉ.

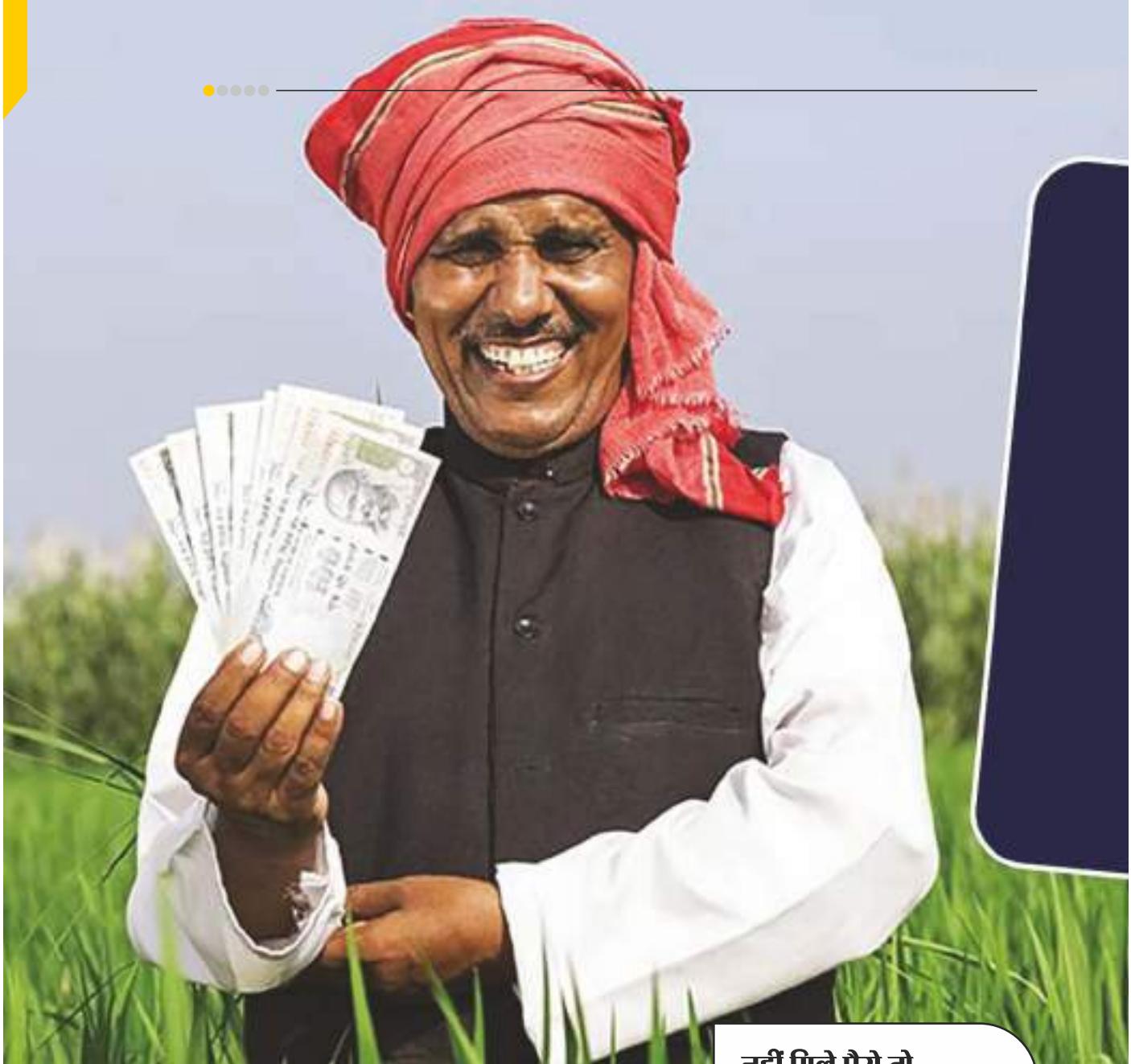
ओ.पी. डहरिया. छत्तीसगढ़ में बीते चार सालों में खेती-किसानी में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। इन वर्षों में जहां खेती का रकबा बढ़ा है, वहीं कृषि उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य में लगभग 30 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल ली जा रही है, खरीफ में सर्वाधिक धान की फसल ली जाती है। धान की फसलों की व्यवस्थित खरीदी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी एक नवम्बर से प्रारंभ होने जा रही है। लगभग 01 करोड़ 10 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।

छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी में आया बदलाव मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है। किसानों को समर्थन मूल्य का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही उन्हें इनपुट सब्सिडी के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। इस योजना के तहत धान की फसल लेने वाले किसानों को 9000 रुपए और धान के अलावा खरीफ की अन्य फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा किसानों को खेती-किसानी के लिए ब्याज मुफ्त ऋण की भी व्यवस्था की गई है। इन सबका परिणाम यह निकला कि जो किसान खेती-किसानी छोड़ चुके थे, वे भी अब खेती-किसानी से जुड़ रहे हैं। वर्ष 2018 में पंजीकृत किसानों की संख्या 16.92 लाख जो बढ़कर अब 25.12 लाख हो चुकी है।

पिछले चार वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने लगभग एक लाख करोड़ की मदद किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग के लोगों को दी गई है। इसके अलावा गांवों में रोजगार के नये अवसर के लिए भी पहल की गई है। गौठानों में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) विकसित किए जा रहे हैं। राज्य में प्रथम चरण में लगभग 300 नये रीपा प्रारंभ किए गए हैं। इनमें से

ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नये-नये अवसर दिए जा रहे हैं। यहीं कारण है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगार देश में सबसे कम है।

किसानों के धान एवं अन्य फसलों के रकबे के सही निर्धारण के लिए गिरदावरी व्यवस्था को मजबूत बनाया गया। वहीं उन्हें धान खरीदी का समय पर कीमत दिलाने की पहल की गई है। धान खरीदी की पूरी व्यवस्था कम्प्यूटरिकृत की गई है। इससे किसानों को धान बेचने के 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों की आर्थिक व्यवस्था में आए बदलाव का असर इस बात से देखा जा सकता है कि इन चार वर्षों में बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरण यंत्रों की खरीदी की है। राज्य सरकार द्वारा खेती-किसानी को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसानों को अत्याधुनिक सिंचाई उपकरण अनुदान पर दिए जा रहे हैं। वहीं पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था के लिए सोलर सिंचाई पम्प भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में इन वर्षों में किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए भी पहल की गई है। किसानों को प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रमाणित बीज समर्थन मूल्य पर खरीदी की भी व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को उनके सिंचाई पम्पों के लिए निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं अन्य वर्ग के किसानों के लिए रियायती दर पर विद्युत उपलब्ध कराया जा रहा है। एक नवम्बर से प्रारंभ हो रही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए इस वर्ष किसानों को ग्रेड-ए धान के लिए 2060 रुपए और कॉमन धान के लिए 2040 रुपए प्रति किंवटल की मान से राशि भुगतान किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए धान खरीदी केन्द्रों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। राज्य में इस वर्ष 2 हजार 497 धान उपार्जन केन्द्रों में खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए राज्य में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी कलेक्टरों को यह हिदायत दी गई है कि धान खरीदी व्यवस्था में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।



रायपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 नामक दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त के तहत कुल 16,000 करोड़ रुपये भी जारी किए। पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करोड़ों किसानों के अटाउंट में डाले गए। इस बीच कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने इस स्कीम के लिए आवेदन तो किया था, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिला।

नहीं मिले पैसे तो क्या करें किसान?

अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन किया था लेकिन आपको इसके पैसे नहीं मिले हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों का पूरा ध्यान रखती है। अपनी देय किस्त नहीं मिलने पर आप पीएम किसान वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान यह भी देख सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थियों की लिस्ट में था भी या नहीं।

पीएम किसान योजना जारी हो गई है 12वीं किस्त



मई में जारी हुई थी पिछली किस्त

इससे पहले पीएम मोदी ने अपनी सरकार की आठवीं वर्षगांठ के अवसर पर मई महीने में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के रूप में 21,000 करोड़ रुपये जारी किए थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और साथ ही केंद्रीय रसायन एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय के तहत 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों (PM KSK) का भी उद्घाटन किया गया।

वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों किसानों, एग्री स्टार्टअप, शोधकारों, नीति-निर्मार्तों और अन्य हितधारकों को संबोधित भी किया। इस मौके पर ह्याभारतीय यूरिया बैग ब्रांड नाम से

अब तक
नहीं
निले
पैसे तो
क्या करें
किसान?

पीएम किसान
योजना मज़ाबूले
और छोटे
किसानों के लिए
थुरू हुई थी

पीएम किसान सम्मान
निधि योजना के तहत
लाभार्थियों को सालाना
6000 रु मिलते हैं।

किसानों को हर
चार महीनों में 2,000
रुपये की तीन समान
किस्तें दी जाती हैं।

पीएम किसान की वेबसाइट पर कैसे करें शिकायत?

पीएम किसान योजना से जुड़ी शिकायत करने के लिए आप ईमेल आईडी: pmkis@pmkis.ict.gov.in पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इसका नंबर 011-24300606, 155261 है। पीएम किसान योजना के लिए टोल फ्री नंबर 1800-115-526 है।

एक राष्ट्र-एक उर्वरक
नामक महत्वपूर्ण
योजना भी लॉन्च की



योग करने से एनर्जी लेवल बढ़ता है और कई दुर्लभ बीमारी कोसों दूर रहती है। योग करने से मन शांत भी रहता है और हमारे विचारों में भी सकारात्मकता आती है। योग के प्रति लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अब ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विदेशों में भी अपनाया जा रहा है।

योगा करते टाइम आप भी तो नहीं करते ये गलती?

यो

ग करना हमारे आपके लिए जितना शरीर और मन के लिए जितना फायदेमंद है उतना ही खतरनाक है गलत तरीके से किया गया योग। इसलिए योग करते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें।

चुस्त या टाइट कपड़े न पहने

योग करते समय कई लोग जो कपड़े पहने रहते हैं उसी कपड़े में योग शुरू कर देते हैं, लेकिन टाइट कपड़े पहन कर योग करने से श्वास लेने और योग करने में आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा आरामदायक और ढिले कपड़े पहन कर ही योग करें।

खाना खाकर योग न करें

कई बार लोग खाना खाकर योग करने लगते हैं लेकिन आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से शरीर में शरीर में ऐंठन महसूस हो सकता है और इसके अलावा, जी मिचलाना या उल्टी जैसी शिकायत भी हो सकती है। इसके पीछे का कारण ये है कि खाना इतनी जलदी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है इसलिए जब भी योग करें खाली पेट करें।

योग के बाद तुरंत नहाय नहीं

कई लोग योग करने के बाद तुरंत नहाने चले जाते हैं, लेकिन ये गलती भूल कर भी न करें। क्योंकि इससे आपकी तबियत काफी बिगड़



मोबाइल रखें दूर

आमतौर पर हमारा ध्यान किसी विषय से भटकाने में मोबाइल फोन की बड़ी भूमिका होती है। योग हमें ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। लेकिन अगर वहां भी मोबाइल रखकर योग किया जाए, तो ध्यान भटकना तय ही मानिए। इसलिए बेहद जरूरी है कि कम से कम योग करते वक्त फोन को 1 घंटे के लिए साइलेंट कर लिया जाए। यकीन मानिए, मोबाइल को खुद से दूर किया जा सकता है। एक घंटे के लिए ही सही अगर मोबाइल से खुद को दूर कर लिया जाए तो दिमागी तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

सकताहै। ऐसा इसलिए है क्योंकि योग करने से हमारे शरीर में ऊर्जा एकत्रित होता है और शरीर गर्म हो जाता है। गर्म के बाद ठंडे तपमान का पानी बॉडी में पड़ने से बीमार हो सकते हैं।

योगा मैट की सफाई का रखें ध्यान

सही ढंग से योग करने के लिए योगा मैट की सफाई बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि योगा मैट से बदबू न आ रही हो और उसे सही ढंग से साफ किया गया हो। खासतौर पर हॉट योग का अभ्यास करने के लिए ये बहुत जरूरी है। हॉट योग का अभ्यास करने पर शरीर से जमकर पसीना निकलता है। अगर मैट की लंबे वक्त तक सफाई न की जाए, तो मैट चिकनी होकर फिसल सकती है। इससे न सिर्फ हमें गंभीर चोट लग सकती है, बल्कि आसन में संतुलन बनाने में भी मुश्किल आ सकती है।



कृषि स्टार्टअप के लिए

500 करोड़ का एकसीलरेटर प्रोग्राम शुरू होगा



केवल 5 फीसदी स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में

देश में तकरीबन 70,000 स्टार्टअप हैं. इनमें से केवल पांच फीसदी ही कृषि क्षेत्र में हैं. बाकी स्टार्टअप सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ई-कॉमर्स और अन्य तकनीक आधारित क्षेत्रों में हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार तकनीक को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार चाहती है कि हमारे स्टार्टअप विद्यमान चुनौतियों का समाधान करते हुए देश-दुनिया के काम आए.

इन क्षेत्रों में भी मिलेगी मदद

स्टार्टअप की पहल से किसानों को मूल्य शृंखला में अपने निवेश और उत्पादन का सबसे अहङ्कार प्रतिफल मिल पाया है. कई स्टार्टअप खेती से जुड़े अन्य सहयोगी कार्यों में जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन, मधुमक्खी पालन और ऐसे अन्य क्षेत्रों में अपनी सेवाएं मुहैया करा रही हैं. इनमें से कुछ स्टार्टअप सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मांडल के तहत सरकार की विभिन्न योजनाओं में साझेदारी करके आधिकारिक रूप से कृषि विकास योजनाओं को बढ़ावा देने में मदद कर रही हैं.

जानकारी दी. एग्री स्टार्टअप की सफल पहलों को आगे बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये का एकसीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा. जिसमें बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ई-नाम व नेफेड जैसी संस्थाओं के साथ एक मार्केटिंग लिंकेज बनाया जाएगा. यह भी बताया एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर करने का प्रयास किया जाएगा.

कृषि क्षेत्र में भी किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये युवाओं और किसानों को कृषि स्टार्टअप करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है. इसके लिये केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आर्थिक सहायता भी मुहैया करवा रही हैं. कृषि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र मार्गदर्शन के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में उड्ढन स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में यह





हमारा कर्का नंबर 1

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से अपने प्रदेश की आम जनता को खुश रखने के लिहाज से देश के मुख्यमंत्रियों में पहले पायदान पर हैं। भूपेश बघेल के बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबसे कम एंटी इनकम्बेंसी है। यह बात क़ाठर-उ-वोटर्स के देशव्यापी सर्वे में सामने आई है।

ANS-C वोटर्स ट्रैकर के अनुसार, छत्तीसगढ़ में केवल 6 प्रतिशत लोगों ने मुख्यमंत्री बघेल के खिलाफ अपनी बात कही है। भूपेश बघेल के पास सभी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले ज्यादा समर्थन है। अगले 12 महीनों में मतदान वाले राज्यों में, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान समेत अधिकतर अन्य मुख्यमंत्रियों को इस पैमाने पर कम स्थान दिया गया है।

पिछले साल भी था जलवा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शासन के सभी स्तरों पर सबसे कम विरोध की लहर का सामना करना पड़ा है। 2021 को भी इसी अवधि में किए गए ट्रैकर में भी बघेल सबसे अच्छा

कौन कितने नंबर पर

ताजा सर्वे में बघेल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनसे केवल 8.3 प्रतिशत उत्तरदाता नाराज हैं। तीसरे स्थान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान हैं। उनके खिलाफ सिर्फ 9.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नाराजगी जाहिर की है। असम के सीएम हेमंत बिस्ता सरमा चौथे स्थान पर हैं। सरमा के मुख्यमंत्री के कार्यकाल से 12.2 उत्तरदाता नारुण हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पांचवें स्थान पर हैं। उनके खिलाफ केवल 12.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के आपत्ति जताई हैं। सूची में सबसे नीचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिनसे 35.4 प्रतिशत उत्तरदाता नाराज हैं।

प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक थे, जिन्हें मतदाताओं के गुस्से का सबसे कम सामना करना पड़ा था।

कैसे किया गया है सर्वे

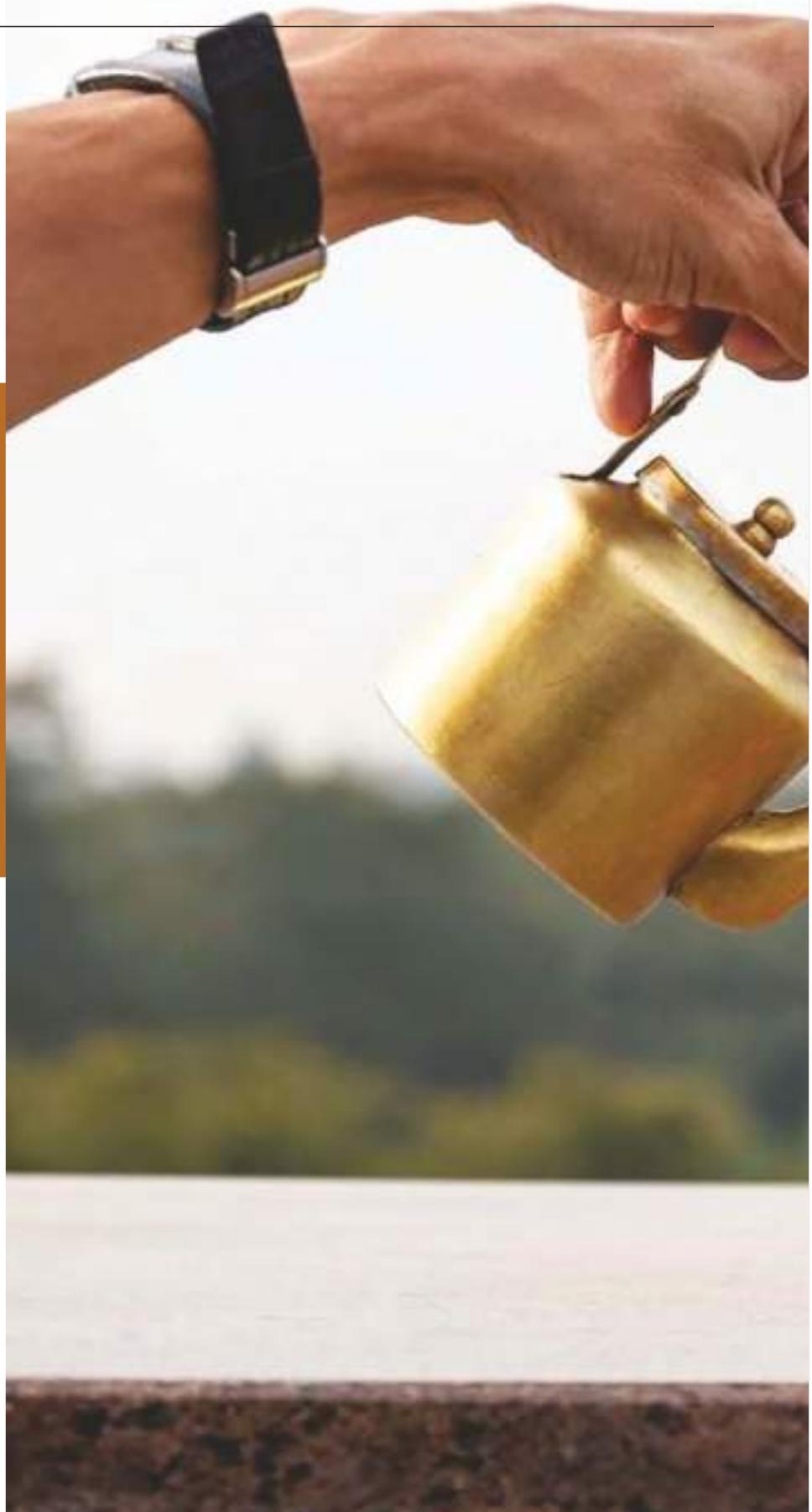
IAN-S-C वोटर्स गर्वनेस ट्रैकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर तिमाही में पचीस हजार से अधिक उत्तरदाताओं का इंटरव्यू लेता है। ट्रैकर 11 भाषाओं में चलाया जाता है। केंद्र, राज्य और हर राज्य में शासन की सत्ता विरोधी भावनाओं को मैप करता है। वर्तमान विश्लेषण जुलाई से सितंबर 2022 तक ट्रैकर डेटा का उपयोग कर किया गया है।

आम आँखमें // नवम्बर // 2022

गूड के
हिसाब से

पीये चाय

चाय एक ऐसा नशा जो  लगभग 80 फीसदी भारतीयों में पाया जाता है. सुबह उठने से लेकर, थकान दूर करने, सिर दर्द ठीक करने, मूड ऑफ है तो चाय, हर समस्या का एक ही मर्ज है चाय. चाय की लोकप्रियता ना सिर्फ भारत में है बल्कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग चाय के शौकीन हैं. आज हम आपको बताएँगे की कैसे मूड में कौन सी चाय आपके लिए फायदेमंद होगी.





थकान दूर करने ब्लैक टी

अगर आप खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो ब्लैक टी आपकी एनर्जी वापस ला सकती है. ब्लैक टी बनाने के लिए 2 कप पानी को अच्छे से उबाल लें अब असमें बहुत थोड़ी सी चाय पत्ती डालकर ऊपर से ढक दें और 3 से 4 मिनट बाद छान लें. आप ब्लैक टी को चीनी मिला कर भी पी सकते हैं और बिना चीनी के भी पी सकते हैं.

गुस्सा शांत करने ऑरेंज टी

अगर आपको गुस्सा आ रहा है और अपने गुस्से को शांत करना चाहते हैं तो ऐसे में ऑरेंज टी आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है. ऑरेंज टी बनाने के लिए

एक बर्तन में पानी लें और इसमें ताजे या सूखे संतरे के छिलके डालें. इसमें एक चुटकी दालचीनी पाउडर या दालचीनी की लकड़ी उबाल लें. लो फ्लेम पर इन्हें 10 मिनट तक पकाएं, ऑरेंज टी तैयार है.

टेंशन दूर करने कैमोमाइल टी

जब भी आप टेंशन में हो तो कैमोमाइल चाय पी लीजिए. कैमोमाइल चाय को तनाव दूर करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. कैमोमाइल चाय बनाने के लिए 240 मिली पानी गर्म करें. ध्यान रखें कि पानी को उबालना नहीं है. अब इस पानी में 1 बड़ा चम्मच कैमोमाइल के सूखे फूल डालें. इसका अक्सिकल जाए तो इसे छान कर सर्व करें.

सोने से पहले लैवेंडर टी

सोने से पहले आपको लैवेंडर टी पीनी चाहिए क्योंकि इसकी खुशबू आपके मन और शरीर को आराम के साथ-साथ ताजगी भी देती है. लैवेंडर फ्लेवर टी बनाने के लिए 2 कप उबलते पानी में आधा चम्मच लैवेंडर डालकर गैस बंद कर दें. अब लैवेंडर का अर्क निकलने तक उसी में रहने दें. इस प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट भी लग सकता है. चाहें तो इसे ऐसे ही पिएं या फिर फ्रिज में ठंडा कर भी पी सकते हैं.

मसाला टी करे

नकारात्मक विचार दूर

अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं या फिर खुद को नकारात्मक महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए इंडियन मसाला टी पीएं. इंडियन मसाला टी बनाने के लिए लौंग, इलायची, काली मिर्च और दाल चीनी हल्का सा भून लीजिए. ठंडा होने पर जायफल और सौंठ मिला कर बारीक पीस लीजिए. अब पानी में पिसा मसाला डालकर उबालें. इसके बाद इसमें चाय पत्ती डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं. आखरी में शक्कर और दूध डालकर 3 से 4 मिनट तक पकाएं और सर्व करें.





तीस-तीस वर्षों के लिए दी जाएगी लीज पर

निजी निवेशक 21 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

छत्तीसगढ़ ट्रूरिजम बोर्ड के 22 मोटल व रिसॉर्ट को लीज पर देने की कार्यवाही शुरू

रायपुर. छत्तीसगढ़ ट्रूरिजम बोर्ड द्वारा अपने 22 मोटल एवं रिसॉर्ट के संचालन के लिए लीज पर दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इन मोटल व रिसॉर्ट को तीस-तीस वर्षों के लिए लीज पर दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के निजी निवेशक 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि पर्यटकों को व्यवसायिक दृष्टिकोण से अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निजी निवेशकों से संचालन के लिए लीज में दिए जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि प्रदेश में पर्यटन विकास की दिशा को सक्षम गति प्राप्त हो सके।

३ ललेखनीय है कि छत्तीसगढ़ ट्रूरिजम बोर्ड द्वारा पूर्व में की गई निविदा के माध्यम से रायगढ़ और सरगुजा में स्थित मोटल के संचालन हेतु सफल निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव को समिति द्वारा मान्य किया गया है। शीघ्र ही इन इकाईयों का संचालन सफल निविदाकर्ताओं को सौंपा जायेगा।

छत्तीसगढ़ ट्रूरिजम बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि निजी निवेशकों द्वारा मितान मोटल चढ़ीरमा (सरगुजा के लिए एक मुश्त लीज प्रीमियम राशि 15,07,777 रुपए, मितान मोटल, कोडातराई (रायगढ़) के लिए एक मुश्त लीज प्रीमियम राशि 25,66,899 रुपए, मितान मोटल कुलीपोटा (जांजीर-चांपा) के लिए एक मुश्त लीज प्रीमियम राशि 19,24,111 रुपए एवं मितान मोटल सरगांव (बिलासपुर) के लिए एक मुश्त लीज प्रीमियम राशि 42,11,121 रुपए पर 35 प्रतिशत वार्षिक किराया प्रस्ताव मंजूरी प्रदान कर दी है। शीघ्र ही इन 04 मोटल का संचालन प्रारंभ हो जाएगा, जिससे देश-विदेश के पर्यटकों को

मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ ट्रूरिजम बोर्ड की 10 संचालित एवं 12 असंचालित कुल 22 इकाईयों को 30 \$ 30 वर्ष की अवधि के लिए तृतीय चरण की निविदा ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित की गई है। अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ शासन की अधिकृत वेबसाइट

eproc.cgstOte.gov.in»»f
एवं छत्तीसगढ़ ट्रूरिजम बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट www.chhottisgOrhtourism.in»»f

से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ ट्रूरिजम बोर्ड के दूरभाष क्र. +91-0771-4224621 एवं मोबाइल नं. +91-9300652548 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।



दिल की बीमारी से मासूमों का जीना था गुरिकल

डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना ने दिया नया जीवन

या

यगढ़ के सोनबरसा की रहने वाली कोमल चौहान दूसरी कक्षा में पढ़ती है। बार बार बीमार रहने से

कोमल के घरबाले पेरेशन रहते थे। इसी तरह से चपले गांव की रहने वाली पायल पटेल भी बीमारी की वजह से हँसना मुस्कुराना भूल गई थी। इन दोनों मासूमों के परिजनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें।

दरअसल पायल और कोमल को दिल की बीमारी थी जिसे डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम स्कूलों में जाकर बच्चों की स्वास्थ्य जांच करती है, इसी जांच

में ये पता चला कि दोनों बच्चियों के दिल में छेद है जिससे उनका विकास नहीं हो पा रहा है और वो बीमार रहती हैं। इसके बाद कोमल और पायल को डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत रायपुर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया और दोनों का निःशुल्क इलाज कराया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शुरू की गई डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना की वजह से ही आज

कोमल और पायल जैसी बच्चों की जान बच रही है और वो अपना नया जीवन शुरू कर पा रहे हैं।

आज जब बच्चों के परिजनों को पता चला कि मुख्यमंत्री खरसिया के चपले गांव में आ रहे हैं तो दोनों बच्चियां भी परिजनों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचीं। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ इन बच्चियों के साथ फोटो खिंचवाई बल्कि इन्हें गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया।

“Electric Vehicle सेगमेंट में तेजी से ग्रोथ देखी जा रही है जिस वजह से वाहन निमार्ता कंपनियां एक के बाद एक अपनी नई गाड़ियां मार्केट में ग्राहकों के लिए लॉन्च कर रही हैं। MG Motor India (एमजी मोटर इंडिया) ने पुष्टि की है कि वह साल 2023 अप्रैल-जून में एक किफायती मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी।

इस मॉडल का नाम MG City EV (एमजी सिटी ईवी) हो सकता

है। जो कि चीन में बिक रही Wuling Air EV पर बेस्ड होगी। यह इलेक्ट्रिक कार लगभग 20kWh - 25kWh की बैटरी क्षमता के साथ करीब 40bhp का पावर दे सकता है। रियल वर्ल्ड कंडीशन में इसकी रेंज करीब 150 किमी होगी।

हाल ही में MG के इस ईवी को भारत के सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इससे उम्मीद है कि भारत में जल्द ही आपको एक नई सस्ती इलेक्ट्रिक कार देखने को मिल सकती है। एमजी की इस ईवी का मुकाबला टाटा ईवी से होगा। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 11 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है। यदि इस कीमत पर इसे लॉन्च किया गया तो नई एमजी इलेक्ट्रिक कार मौजूदा टाटा ईवी को टक्कर देगी जिसमें टियागो ईवी, टिगोर ईवी और नेक्सन ईवी शामिल हैं। टाटा की इन सभी इलेक्ट्रिक कारों की कीमत इस समय 8.49 लाख रुपये से 17.50 लाख रुपये के बीच है।

कंपनी अपने मास-मार्केट ईवी के लिए बैटरियों को स्थानीय वेंडर्स से लेगी, ताकि कॉम्पिटिव प्राइसिंग हासिल की जा सके। ऑटोमेकर का लक्ष्य अपने भारतीय ईवी खरीदारों को कम कीमत पर एक इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध कराना है। ऑटोमेकर को उम्मीद है कि उसकी नई

टाटा ईवी को टक्कर देने आ रही है एमजी की छोटी इलेक्ट्रिक कार



एमजी सिटी ईवी की “अच्छी बिक्री” होगी। गुजरात में एमजी का हलोल स्थित प्लांट

इलेक्ट्रिक कार के मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में काम करेगा।



रोज खाता है 1000 रुपये का चारा मेले में छाया 10 करोड़ का मैसा

हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नरेंद्र सिंह मेले में अपने भैसे गोलू टू को लेकर पहुंचे, जो कि मेले में आकर्षण का केंद्र रहा। 10 करोड़ की मीमत वाले भैसे गोलू टू को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा और वह चर्चा का विषय बना रहा। बता दें कि पानीपत के रहने वाले किसान नरेंद्र सिंह पद्मश्री सम्मानित किसान हैं।

भैसे पर प्रतिदिन का खर्च 1000 रुपये का है

नरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके भैसे का नाम गोलू टू इसलिए है, क्योंकि इसके दादा का नाम गोलू वन था और ये अपने दादा गोलू वन से भी शानदार है। इसलिए इसका नाम इस के दादा पर रखा है। नरेंद्र सिंह ने बताया कि उनका भैसा शुद्ध मुर्ग प्रजाति का है और इसकी मां प्रतिदिन 26 किलो दूध देती है। गोलू हर रोज 30 किलो सूखा हरा चारा 7 किलो गेहूं चना 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर खाता है। गोलू टू का रोज का खर्च लगभग 1000 रुपये का है।

नरेंद्र सिंह कहते हैं कि गोलू टू के सीमन से उनको काफी आमदनी हो रही है और काफी आमदनी होगी। नरेंद्र सिंह के अनुसार

भैसे को देखने के लिए आ रही भीड़

किसान मेले में आने वाला हर व्यक्ति भैसे की कद काठी देखकर चकित है और हर कोई गोली टू के बारे में जानना चाहता है। नरेंद्र सिंह कहते हैं कि उनको जानवर का शैक है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने गोलू वन तैयार किया जो गोलू टू का दादा था। पिछले दिनों उसकी मृत्यु हो गई। गोलू वन को लेकर वह जगह-जगह घूमे और उन्होंने उसका सीमन भी काफी जगह दिया है। गोलू वन के बाद उन्होंने पीसी 483 तैयार किया, जोकि गोलू टू का पिता है और उसको बरेंद्र ने हरियाणा सरकार को भैसो की नस्ल सुधारने के लिए उपहार में दे दिया।

गोलू टू कहीं भी जाता है तो उसके लिए एक पानी का टैंकर मंगवाया जाता है। क्योंकि भैसे को जर्मा ना लगे, इसलिए बार-बार पानी डाला जाता है और पानी पिलाया जाता है।

खरीदारों ने इसकी कीमत 10 करोड़ तक आंकी है, लेकिन वह इसको बेचने के लिए तैयार नहीं हैं।

2019 में नरेंद्र सिंह को मिला था पद्मश्री अवार्ड

नरेंद्र सिंह बताते हैं कि मेले में गोलू टू लाने का मकसद उनका है कि वह इसे और किसानों को दिखा सकें। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र में कार्य करने के लिए उनको 2019 में सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया था। उनकी इच्छा है कि

अच्छे सीमन का प्रयोग करके अच्छे भैसे और भैस तैयार हों।

गोलू टू की उम्र 4 साल 6 महीने है। उसकी ऊंचाई 5 फीट 6 इंच के आसपास है और 14 फुट लंबाई है। इसका वजन 15 कुंटल है। इसके पिता पीसी 483 थे। इसके पिता का वजन 12 कुंटल है। 2 साल से जो भी प्रदर्शनी लगती है, उसमें इस भैसे को लेकर जाते हैं। वह कहते हैं कि इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ है, लेकिन उसे बेचेंगे नहीं चाहे कोई कितने भी पैसे दे।

मुंबई. ऐसे समय में जब जमीन के लिए भाई-भाई का दुश्मन बन जाता है. जमीन को कीमती धन माना जाता है वहाँ किसी जानवर के नाम जमीन होना थोड़ा अजीब लगा ना? जी हाँ, हमें भी लगा. महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के एक गांव में बंदरों को 32 एकड़ जमीन बंदरों के नाम है. ये उन्हें सम्मान देने के रूप में देखा जाता है. गांव लगभग 100 बंदरों का घर है. हालांकि उनकी संख्या पिछले कुछ वर्षों में घट गई है क्योंकि जानवर लंबे समय तक एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं.

ठाठ हों तो ऐसे!

इस गांव के बंदरों के नाम है 32 एकड़ जमीन

रिकॉर्ड में है इस बात का प्रूफ

उस्मानाबाद के उपला गांव के लोग सिमियन निवासियों का बहुत आदर करते हैं और कभी-कभी शादियों में उनका सम्मान भी करते हैं. उपला ग्राम पंचायत के पास मिले लैंड रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से यह बात कही गई है कि 32 एकड़ भूमि गांव में रहने वाले सभी बंदरों के नाम है. गांव के सरपंच (प्रमुख) बप्पा पड़वाल ने पीटीआई को बताया, हृदस्तावेजों में साफ तौर पर कहा गया है कि जमीन बंदरों की है, लेकिन यह पता नहीं है कि जानवरों के लिए यह प्रावधान किसने और कब किया. उन्होंने कहा कि अतीत में, बंदर गांव में किए जाने वाले सभी अनुष्ठानों का हिस्सा थे.

सबसे पहले मिलता है गिप्ट

उन्होंने बताया कि उस भूमि पर वन विभाग ने वृक्षारोपण का काम किया है और प्लाट पर एक छोड़ा हुआ घर भी था, जो अब ढह गया है. सरपंच ने कहा, हृपहले, जब भी गांव में शादियां होती थीं, तो बंदरों को पहले उपहार दिया जाता था और उसके बाद ही समारोह शुरू होता था. अब हर कोई इस प्रथा का पालन नहीं करता है. हाँ अगर कोई बंदर किसी के दरवाजे पर आता है तो ग्रामीण बंदरों को खाना खिलाते हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी उन्हें खाने से मना नहीं करता है.





रोटी पर 5
फीसदी जबकि

पराठे पर 18 फीसदी लगेगा जीएसटी

“ क्या प्रोजन पराठे पर रोटी या चपाती के समान जीएसटी दर पर कर लगाया जाना चाहिए ? शायद आप समझ नहीं पाए. आपको बता दें कि अगर आप पराठे खाने के शौकीन हैं तो आगे आने वाले समय में आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है. गुजरात की अपीलेट अथोरिटी ऑफ एडवांस ललिंग (आआएफ) का कहना है कि रोटी और पराठे में काफी अंतर है इसलिए इस पर टैक्स लगाना चाहिए.

हा

लांकि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों का कहना है कि दर अधिक नहीं हो सकती क्योंकि दोनों के लिए मुख्य सामग्री साबुत गेहूं का आटा है। यह फैसला अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज की अपील पर आया है जिसके लिए 20 महीने से अधिक लडाई चल रही थी। फैसले के अनुसार पराठे पर अब 18 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। हालांकि, रोटी पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

यह कंपनी कई तरह के रेडी टु कुक यानी फ्रोजन पराठे बनाती है। कंपनी की दलील थी कि रोटी और पराठे में ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों आठे से ही बनती हैं, इसलिए पराठे पर भी पांच फीसदी जीएसटी लगना चाहिए। दलील में आगे कहा गया कि ना केवल पराठे और रोटी को बनाने को बनाने की प्रक्रिया मिलती जुलती है बल्कि उनका इस्तेमाल और उपभोग का तरीका भी समान है। लेकिन एएआर ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया और साफ किया कि पराठे पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

याचिकाकर्ता अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज की अपील पर यह फैसला लिया गया है। जबकि पराठे के बिजनेस से जुड़ी कंपनियों का कहना है कि पराठे पर रोटी (5%) से अधिक जीएसटी नहीं लगाई जानी चाहिए क्योंकि दोनों ही गेहूं के आठे से बनते हैं। इसलिए इन पर टैक्स समान होना चाहिए।

दूध के साथ भी ऐसी ही बहस

रोटी पराठे जैसा ही जीएसटी विवाद दूध और फ्लेवर्ड दूध को लेकर भी है। गुजरात के जीएसटी प्राधिकारियों ने सुगंधित दूध पर 12 फीसदी जीएसटी को वैध माना है, जबकि दूध पर कोई कर नहीं लगता है। यानी अब अगर आप किसी स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो आपके बिल पर पांच फीसदी टैक्स ही लगेगा। चाहें आप रोटी खाएं या पराठा, ये फैसला सिर्फ़ पैकड़ और फ्रोजन पराठे पर मान्य है।



कैसे किया अंतर?

याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी कंपनी 8 तरह के पराठे बनाती है जिसमें मालबार पराठा, मिक्स पराठा, ओनियन पराठा, प्लेन पराठा, आलू पराठा, लच्छा पराठा शामिल हैं। इसको बनाने में आठे का इस्तेमाल होता है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि ये रोटी की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें रॉ-मटेरियल के तौर पर आटा, तेल, सब्जी का ही इस्तेमाल होता है। इन फोजन पराठों को घर में गरम कर खाया जा सकता है। इसलिए इसमें एसजीएसटी या सीजीएसटी नहीं लगना चाहिए।

15 सितंबर को एक नए फैसले में, गुजरात के अग्रिम निर्णय के लिए एएआर ने पैक / जमे हुए पराठों और रोटियों के बीच स्पष्ट अंतर किया। अपीलेट प्राधिकरण के आदेश ने गुजरात के अथोरिटी फॉर एडवांस रॉलिंग के जून 2021 के आदेश को प्रभावी ढंग से बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि इस तरह के पैकेज्ड पराठों को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक 3-4 मिनट पकाने की आवश्यकता होती है और इसमें गेहूं की मात्रा भी 36 प्रतिशत से 62 प्रतिशत के बीच होती है।

अरेंज मैरिज करने से पहले जान लें ये बातें

अरेंज मैरिज का मतलब होता है, परिवार की सहमति से होने वाली शादी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि भविष्य में कोई परेशानी आने पर परिवार वालों का पूरा सपोर्ट मिलता है। शायद इसी वजह से लोग अब अरेंज मैरिज पर यकीन करने लगे हैं। अरेंज मैरिज से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। आज के जमाने में अरेंज मैरिज का नाम सुनकर अजीब सा लगता है। ऐसा

इसलिए क्योंकि इन दिनों लव मैरिज का ट्रेंड है। लड़का-लड़की न केवल अपनी पसंद के अनुसार अपने जीवनसाथी की तलाश कर रहे हैं बल्कि वह इसे सही भी मानते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मॉडर्न

जमाने वाले इस दौर में भी अरेंज मैरिज करने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। हालांकि, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्योंकि

लव मैरिज के मुकाबले अरेंज मैरिज के सफल होने के ज्यादा चांस होते हैं। यही एक वजह भी है कि अरेंज मैरिज आज भी दुनियाभर

में पॉपुलर है। स्टैटिस्टिक्स ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अरेंज मैरिज में तलाक की दर मात्र 6 फीसदी है जबकि प्रेम विवाह कब दूट जाए इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि आज बहुत से लोग अपने पैरेंट्स द्वारा चुने गए व्यक्ति से ही शादी करते हैं।



दिल नहीं टूटता

सुरक्षित होता है भविष्य

शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, जिसमें न केवल दो परिवार एक होते हैं बल्कि उनके बीच एक अदूर इश्ता भी बनता है। ऐसे में जब शादी पकड़ी होती है, तो माता-पिता की जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके बच्चे किसी भी हाल में खुश रहें। मुश्किल घड़ी में अरेंज मैरिज में लोगों को अपने बड़ों का समर्थन और साथ मिलता है जबकि लव मैरिज में ऐसा नहीं होता।

आज के समय में रिश्ते निभाना सबसे मुश्किल काम है और जब पति-पत्नी के रिलेशन की बात हो, तो इसमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खासतौर से लव मैरिज में हर दिन एक चुनौती सामने खड़ी होती है जबकि अरेंज मैरिज की सच्चाई है कि इसमें आपके दिल टूटने की संभावना बहुत कम होती है। यहीं सबसे बड़ा कारण भी है कि लोग अरेंज मैरिज पर यकीन करने लगे हैं। यहां तक की बॉलीबुड ने भी इसे अच्छे से अपनाया है।

संस्कृति को जीवित रखती है

संस्कृति वह आधार है, जिस पर व्यक्ति अपने विश्वासों-मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर टिका होता है। यह वह सिद्धांत हैं, जिसे विदेश जाने पर भी व्यक्ति नहीं भूलता। आप भारतीयों के दिल से भारत को निकाल नहीं सकते। एनआरआई नागरिकों के लिए अरेंज मैरिज भारत को उनके दिलों में जिंदा रखने का एक तरीका है। इससे वह अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहते हैं।

शादी सही समय पर होती है

लव मैरिज में पहले लोग डेटिंग करते हैं और फिर करियर बनाने के चक्कर में शादी को रोककर रखते हैं। ऐसे में लड़का या लड़की की उम्र बढ़ती चली जाती है, जो हर माता-पिता के लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। जबकि अरेंज मैरिज में ऐसा कोई मौका नहीं मिलता। आपका परिवार आपकी शादी के बारे में तभी सोचने लगता है, जब आप सेटल हो जाते हैं और शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं।

माता-पिता खुश होकर जिम्मेदारियां निभाते हैं

जब पेरेंट्स खुद आपके लिए रिश्ता चुनते हैं, तो शादी से जुड़ी हर जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। वह हर जिम्मेदारी को आपस में बांटते भी हैं। लेकिन लव मैरिज में माता-पिता की सोच अलग हो सकती है। वहीं हो सकता है कि माता या पिता में से कोई एक शादी की रस्मों में दिलचस्पी ही ना ले। लेकिन अरेंज मैरिज में इसकी संभावना बहुत कम होती है। यहीं तो बड़ी बजह भी है कि लव मैरिज के जमाने में अरेंज मैरिज की पुरानी परंपरा आज भी उतनी ही पॉपुलर है। आम इंसान ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटी तक अरेंज मैरिज करके खुशहाल जीवन बिता रहे हैं।

“ रायपुर. कटहल काफी हेल्दी फूड है. जिसमें भरपूर मात्रा में पोषण होता है. इसके पोषण के कारण ही इसे शाकाहारी लोगों का मीट कहा जाता है. वहीं, खाना बनाने के बाद यह दिखने में भी नॉन-वेज की तरह ही लगता है. लेकिन, इतना पौष्टिक होने के बाद भी कुछ लोगों को कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए. क्योंकि, इससे उन्हें सांस आनी भी बंद हो सकती है. आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि कटहल के अंदर कौन-से पोषक तत्व होते हैं और इसे किन लोगों को नहीं खाना चाहिए.

कटहल को खायों कहा जाता है शाकाहारी लोगों का मीट?

कटहल का गुदा दिखने में बिल्कुल मीट की तरह होता है. साथ ही कटहल खाने से मीट की तरह ही काफी पोषण मिलता है. जैसे- प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, राइबोफ्लेविन आदि.

एलर्जी के कारण सांस हो सकती है बंद

जिन लोगों को लैटेक्स या बिर्च पोलन से एलर्जी होती है, उन्हें कटहल का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए. क्योंकि, कटहल खाने से भी उन्हें एलर्जी के लक्षण झेलने पड़ सकते हैं. आपको बता दें कि एलर्जी के कारण रेस्प्रेटरी सिस्टम काफी प्रभावित होता है और कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी या सांस आनी बंद हो सकती है.

गर्भवती महिलाएं

गर्भवती या बच्चे को स्तनपान करा रही महिलाओं को कटहल नहीं खाना चाहिए या फिर आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए. क्योंकि, इससे गर्भपात या बच्चे के स्वास्थ्य पर नुकसान पड़ने का खतरा होता है. हालांकि, इसके सपोर्ट में कोई शोध उपलब्ध नहीं है. बस यह बात पुराने जमाने से चली आ रही है.

कटहल को बिल्कुल ना खाएं ये लोग सांस आनी हो जाएगी बंद

डायबिटीज के मरीज

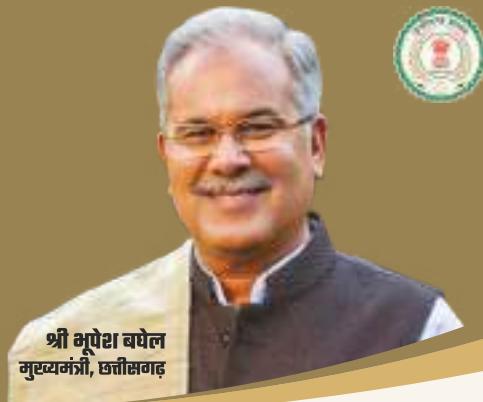
डायबिटीज के मरीजों को कटहल का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए. अगर मधुमेह रोगी रोजाना और भारी मात्रा में कटहल खाते हैं, तो इससे ब्लड शुगर लेवल काफी नीचे जा सकता है. क्योंकि, कटहल में एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर को नीचे लाते हैं.

किडनी रोग के मरीज

अगर आप किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं, तो कटहल नहीं खाना चाहिए. क्योंकि, इसमें पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है. जो कि खून में पोटैशियम लेवल को बढ़ा सकता है और यह किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है. यह स्थिति हाइपरकलोमिया कहलाती है, जो कि पैरालाइटिस और हार्ट फेलियर का कारण भी बन सकती है.



बहुत कुछ हो रहा देश में पहली बार मिलाल प्रस्तुत कर रहे हमारे नवाचार



श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



जनता गांधी किसान न्याय योजना
राज्य के किसानों को विभिन्न फसलों के लिए
उनके खातों में सीधे इनपुट सब्सिडी



गोधन न्याय योजना
गौपालकों व ग्रामीणों से गोबर व गौमूत्र की
खरीदी व गौठानों को "रुरल इंडस्ट्रियल पार्क"
में तब्दील करने की योजना



**स्वामी आत्मानंद
अंग्रेजी माध्यम विद्यालय**
आधुनिक शिक्षा का पर्याय बनी
स्वामी आत्मानंद स्कूलों की सफल शृंखला,
अब महाविद्यालयों तक उन्नयन



नए जिले, ननदीक सहकार
प्रदेश में प्रशासनिक सुव्यवस्था के लिए नए
जिलों व तहसीलों का गठन



मुख्यमंत्री जलम द्वारश्य योजना
प्रदेश के नगरीय इलाकों, झुग्गी-झोपड़ियों में
मरीजों का मोबाइल क्लिनिक से घर बैठे इलाज



बिजली बिल हॉफ योजना

400 यूनिट से कम बिजली की खपत पर
50 फीसदी की छूट



मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना

ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों के हाट-बाजारों में
स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों का इलाज



मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लिनिक योजना

मोबाइल अस्पतालों के माध्यम से कुशल महिला
चिकित्सकों के द्वारा महिलाओं की जांच-इलाज
एवं मुफ्त दवाइयों का वितरण।



तुंदूट सहकार, तुंदूट द्वार योजना

इस योजना के जरिए नागरिकों तक परिवहन संबंधी
22 सेवाओं को पहुंचाने का काम किया जाता है



जनता गांधी ग्रामीण भूमिहीन

कृषि नजदीक न्याय योजना
खेतिहर मजदूरों को हर वर्ष एक मुश्त
7 हजार रुपये की आदान सहायता

आपका अपना ORGANIC किसाना स्टोर



ORGALIFE®

A WIDE RANGE OF CERTIFIED ORGANIC & ECO FRIENDLY PRODUCTS



*T&C Apply

#Organic किसाना स्टोर

**FREE
HOME
DELIVERY**
(Minimum Order ₹1000)

Order On ► www.orgalife.in

Scan & Shop Now



Shop No.15, Ram Bag Parisar,
Opp, Shri Ram Mandir, VIP Road, Raipur

